

मुकदमों का विवरण

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम.

एसएयू। सुमनबाई पांडुरंग पेटर और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 6070)

21 सितंबर, 2023

[बी. आर. गवई और संजय करोल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या कानून के बनाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करने पर पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के अभाव में, उच्च न्यायालय एक अपील यू/एस में उसी पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता था। 100, सी. पी. सी. विशेष रूप से, जब दो न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के तथ्यों को उलटने की मांग की गई थी; और आगे, चाहे परीक्षण रिकॉर्ड को बुलाए बिना और उस पर विचार किए बिना, तथ्यों के तथ्यों को उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उलट दिया जा सकता था। 100, सीपीसी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.100–कार्यक्षेत्र:

आयोजित किया गया: दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार में बैठने वाला न्यायालय प्रवेश के समय कानून का पर्याप्त प्रश्न तैयार करता है, सिवाय इसके कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर—ऐसे प्रश्न तैयार करने के बाद, न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर पक्षकारों को मिलने और उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद उन्हें सुनने के लिए आगे बढ़ेगा—इस तरह की सुनवाई के बाद ही दूसरी अपील का निर्णय लिया जाएगा—इसके अलावा, सामान्य रूप से, इस तरह के अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय तथ्य के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि, यदि वह कानून के संबंध में ऐसा करने के लिए कोई सम्मोहक कारण बताता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद ही, जिसके विश्लेषण पर ऐसे न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है –s.100 (5) सुझाव देता है कि प्रवेश और सुनवाई के समय प्रश्नों को तैयार करने के बीच एक अंतर है, क्योंकि इसका परंतु न्यायालय को सुनवाई के समय अतिरिक्त प्रश्न तैयार करने का अवसर देता है, जिस पर पक्षों को भी सुनना होगा—जिसका अर्थ है कि प्रवेश के समय तैयार किए गए प्रश्न, बाद में प्रश्नों को तैयार करने के ऐसे बिंदु पर, पक्षों को पहले से ही पता हैं और उनके पास समय 489 है।

488

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटकर 490 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

उसी पर दलीलों को संबोधित करने की तैयारी करना—यह तर्क के दौरान है कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा खोजा जाता है और उस संबंध में एक प्रश्न तैयार किया जाता है, जिसमें पक्षों को उस प्रश्न को पूरा करने के लिए समय दिया जाता है—वर्तमान मामले में, पक्षों को अदालत द्वारा बनाए गए प्रश्नों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय नहीं दिया गया था—सुनवाई की दूसरी तारीख को कानून के प्रश्न बनाए गए थे, पक्षों की सुनवाई ठीक तब और वहाँ की गई थी, और दूसरी अपील का निपटारा निर्णय को निर्देशित करने और तथ्य के अंतिम छोर को उलटने के साथ किया गया था—इसके अलावा, विवादित निर्णय ने वादी की ओर से अनुबंध करने की तैयारी और इच्छा के संबंध में समवर्ती तथ्यों को उलट दिया, जिसमें अपवादात्मक परिस्थिति या विकृति को इंगित किए बिना। [पैरा 21, 23–25, 27, 28]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.100–दूसरी अपील–सिद्धांतों को दोहराया गया।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पंचगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी और अन्य। (1997) 4

एससीसी 713:[1997] 2 एस. सी. आर. 12; गुरदेव कौर बनाम काकी (2007) 1 एस. सी. सी. 546:[2006]

1 पूरक।एस. सी. आर. 27; रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य। (2019) 17 एससीसी 71:[2019] 9 एस. सी. आर. 776; संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एस. सी. सी. 17:[2001] 1 एस. सी. आर. 948; केरल सरकार बनाम जोसेफ 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 961; चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.

1273; उमरखान बनाम बिमिल्लाबी (2011) 9 एससीसी 684:[2011] 9 एससीआर 551; शिव

कोटेक्स बनाम तिरगुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2011) 9 एससीसी 678:[2011] 10 एस. सी. आर. 787; गजाराबा भिक्खुभा वढेर बनाम सुमारा उमर अमाद (2020) 11 एस. सी. सी. 114; किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम।रुफ्राइट (पी) लिमिटेड (2009) 16 एससीसी 280; यू. आर. विरुपाक्षप्पा बनाम सर्वमंगला (2009) 2 एस. सी. सी. 177:[2008] 17 एससीआर 877; महबूब-उर-रहमान बनाम अहसानुल गनी (2019) 19 एससीसी 415; बी. सी.

शिवशंकर बनाम बी. आर. नागराज (2007) 15 एससीसी 387:[2007] 3 एससीआर 389;

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल बनाम पटेल रमनभाई मथुरभाई (2020) 16 एस. सी. सी. 255:[2019] 13 एस. सी. आर. 152; कोंडीबा दगडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान

गुजर (1999) 3 एससीसी 722:[1999] 2 एस. सी. आर. 728; दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली (2010) 12 एस. सी. सी. 740:[2010] 7 एस. सी. आर. 222; हमीदा बनाम मोहम्मद।खलील (2001) 5

एससीसी 30; अवतार सिंह और ओआरएस बनामबिमला देवी और अन्य। (2021) 13 एससीसी 816; नजीर मोहम्मद बनाम जे. कमला (2020) 19 एससीसी 57; अमर सिंह बनाम दलीप

सिंह (2012) 13 एस. सी. सी. 405-पर भरोसा किया।

रवि सेतिया बनाम मदन लाल (2019) 9 एससीसी 381; सुखबीर सिंह बनाम बृज पाल

सिंह (1997) 2 एस. सी. सी. 200:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 863-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 के एस. ए. <आई. डी. 3 में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2022 से 2023 की सिविल अपील No.6070।

रूप:

प्रफुल्ल एस. कुबलकर, सत्यजीत ए. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, अभिनव के. मुत्यालवार, गजानन एन. तीर्थकर, विजय राज सिंह चौहान, युगांत ढिल्लन, सुश्री ऐश्वर्या शिंदे, सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।रजत जोसेफ, ऋषिकेश चिताली, विजय कारी सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

संजय करोल जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस न्यायालय के विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं: 2.1 क्या कानून के बनाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करने पर पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के अभाव में, उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (इसके बाद "सी. पी. सी.") के तहत पसंद की गई अपील में इसका फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता था, विशेष रूप से, जब दो न्यायालयों द्वारा दिए गए तथ्यों को उलटने की मांग की गई थी?

2.2 चाहे किसी भी परीक्षण रिकॉर्ड के अभाव में या समन किए बिना और परीक्षण रिकॉर्ड को देखे बिना, 491 के मुद्दे पर तथ्य की बारीकियां।

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटर [संजय करोल जे.] 492

वादी की बिक्री विलेख को निष्पादित करने की तैयारी और इच्छा को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उलट दिया जा सकता था?

3. हालाँकि, शुरू में प्रतिवादियों की अपील में, जिसे पहली बार 26 अप्रैल 2022 को सूचीबद्ध किया गया था, उच्च न्यायालय ने मामले को 29 सितंबर 2022 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन इसे अगले दिन, यानी 30 सितंबर, 2022 के लिए स्थगित कर दिया, जब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद, अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़े और वादी के पक्ष में दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए तथ्यों को उलट दिया।

4. इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, बॉम्बे (नागपुर पीठ) 1 में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित 30 सितंबर 2022 के एक फैसले और आदेश पर हमला करने का प्रयास करती है, जिसमें निचली अदालतों द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन, गढ़चिरौली द्वारा 3 सितंबर, 2014 के फैसले और प्रधान जिला न्यायाधीश, गढ़चिरौली द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 के फैसले के माध्यम से समवर्ती निर्णय वापस किए गए थे।

फैक्टुअल मैट्रिक्स

5. प्रत्यर्थी, सुमनबाई पांडुरंग पेटकर (मूल मुकदमे में प्रतिवादी) 4 ने ₹ 6,60,000—विवाद की संपत्ति विषय वस्तु, यानी 3 एकड़ भूमि अपीलार्थी (मूल मुकदमे में वादी) को बेचने पर सहमति व्यक्त की थी।

6. स्थानांतरण के लिए, संभागीय आयुक्त, नागपुर मंडल, नागपुर ने आवश्यक अनुमति प्रदान की। निष्पादन के विभिन्न प्रयासों के बावजूद, वे नहीं हुए और इस तरह वादी ने उस प्रभावी अधिनियम को नोटिस जारी किए, जो उत्तरदाताओं को 16 दिसंबर, 2009 को 11 बजे संबंधित प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता के साथ दिए गए थे: 30 में विलेख को निष्पादित करने के लिए हूं। इस तरह के नोटिसों का पालन नहीं किया गया क्योंकि प्रतिवादियों ने कथित रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के कार्यालय में आने से बचने की कोशिश की।

1 संक्षिप्तता के लिए, "विवादित निर्णय"

2 इसके बाद "विचारण न्यायालय" के रूप में संदर्भित 3 इसके बाद, "प्रथम अपीलीय न्यायालय"

4 इसके बाद "प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित 5 इसके बाद, "वादी"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

7. यह इस प्रकार है कि वर्तमान मुकदमे का विषय वादी के नेतृत्व में हुआ।

ट्रायल कोर्ट और पहला अपीलीय कोर्ट

8. निचली अदालत ने 5 मुद्दे तैयार किए। मुद्दों का एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व, संबंधित निर्णय और उसके कारण, संक्षेप में, नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	मुद्दे	निष्कर्ष	कारण।
1	क्या वादी यह साबित करता है कि प्रतिवादी नं. 1 ने रुपये के विचार के लिए वादी के पक्ष में एक कृषि ई. एम. ई. एन. टी. ए. एल. ए. एन. डी. एस. यू. आर. वी. ई. वाई. नंबर. 236/2 क्षेत्र 1.19 एच. आर. ओ. एफ. एन. ए. वी. जी. ए. एन. में प्रवेश किया है।	हाँ।	पीडब्लू-1 सुरेश और पीडब्लू-2 सुधाकर ने पदच्युत कर दिया है कि भूमि के संबंध में एक समझौता किया गया था और उनके बीच समझौता नहीं हुआ था। भले ही उल्हास श्रीनिवास अथाले (पीडब्लू-3) ने सकारात्मक रूप से अंगूठे के निशान की पहचान नहीं की है क्योंकि यह वही है जिसे प्रतिवादी नं. 1, अर्थात् सुमनबाई जो यह स्थापित नहीं करती हैं कि उन्होंने अपने अंगूठे के निशान नहीं लगाए थे।
2	क्या वादी यह साबित करता है कि 29.03.2004 प्रतिवादी पर नहीं। 1 ने वादी के पक्ष में बेचने के समझौते को निष्पादित किया है और Rs.60,000/- की बकाया राशि का वादी द्वारा उसी दिन प्रतिवादी को भुगतान किया गया था?	हाँ।	यह स्पष्ट है कि, जारी किए गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार, समझौता किया गया था, और यह कहते हुए कि आर एस। 60,000/- प्रतिवादी द्वारा प्राप्त एस. टी. ए. एन. डी. एस. निष्कर्षतः उक्त राशि का भुगतान किया गया था।

2 ए.	क्या वादी यह साबित करता है कि उसने आर एस का भुगतान किया है। 1, 0 0, 0 0 0 o n 17.01.2005, एक और Rs। 1, 0 0, 0 0 0 / – एन 07.05.2005, 2, 000/– रुपये 12.06.2008 पर और 8,000/– रुपये 12.06.2008 पर प्रतिवादी नं. 1 उसके पति प्रतिवादी सं. के माध्यम से। 2? यदि हां, तो पक्षों के अधिकारों पर इस भुगतान का कानूनी प्रभाव क्या है?	नहीं।	यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि उक्त राशि कहाँ से थी, और न ही किसी भी गवाह की उपस्थिति में उसी के रूप में भुगतान किया गया था। 07.05.2005 पर भुगतान की गई राशि का भुगतान स्पष्ट रूप से चेक द्वारा किया गया था लेकिन रसीद से चेक संख्या अनुपस्थित है। ऐसी राशि के भुगतान को दिखाने के लिए कोई पासबुक या विवरण रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता है। उस हस्ताक्षर में जिसमें इस तरह की राशि की प्राप्ति के संबंध में समझौते के अंतिम पृष्ठ पर समर्थन किया गया था, स्पष्ट नहीं है।
3	क्या वादी यह साबित करता है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है?	हाँ।	सुरेश की (पीडब्लू 1) गवाही में प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति के साथ वादी ने प्रतिवादी को नोटिस देकर विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा था और

			यह तथ्य भी कि उसने रुपये के रिकॉर्ड चेक पर रखा है, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह हमेशा अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है।
--	--	--	--

4	क्या वादी विशिष्ट राहत का हकदार है जैसा कि माँगा गया है?	हाँ।	प्रश्न Nos.1, 2 और 3 में एफ़ाई रेमेटिव में प्रश्न संख्या 4 भी एफ़ाई रेमेटिव में है।
5	कौन सा आदेश और फरमान? सूट आंशिक रूप से	आनुपातिक लागतों के साथ निर्धारित।	-----

9. वादी को, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 15 दिनों के भीतर अदालत में 6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था और इस तरह की जमा राशि पर, प्रतिवादी को उक्त राशि को वापस लेने का हकदार होने के लिए बिक्री विलेख को अनिवार्य रूप से निष्पादित करना था। 10. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के अलावा दो मुद्दों को जोड़ा, अर्थात् (क) क्या मुकदमा सीमा के भीतर है? ; और (ख) क्या विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी? यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को बाधित नहीं करते हुए, परिणामस्वरूप दूसरे मुद्दे का नकारात्मक उत्तर देते हुए, यह भी अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा दायर करने की अवधि सीमा के भीतर थी। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

विवादित निर्णय

11. दूसरी अपील में, न्यायालय ने चार प्रश्न तैयार किए, जो प्रकृति में सारवान थे, और यह अभिनिर्धारित किया कि निचली अदालतों द्वारा वापस किए गए समवर्ती निर्णय "कानून के पूर्ण दुरुपयोग" और "गलत विचार" और पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य की सराहना पर आधारित थे। रवि सेतिया बनाम मदन लाल 6 पर यह कहने के लिए भरोसा रखा गया था कि विकृत तथ्यों/पूर्ण गबन/साक्ष्य पर गलत विचार, या प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने में विफलता के मामलों में, दूसरी अपील में एक अदालत साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और वादी के विशिष्ट कार्य निष्पादन के मुकदमे को खारिज कर दिया गया।

12. अन्य आधारों के अलावा, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय का निर्णय विभिन्न न्यायालयों द्वारा तय किए गए कानून के विपरीत है।

6 (2019) 9 एस. सी. सी. 381 दो न्यायाधीशों की पीठ 495

इस न्यायालय के निर्णयों के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न सुनवाई की दूसरी तारीख को तैयार किए गए थे, जिससे धारा 100 सी. पी. सी. के प्रावधानों का उल्लंघन होता है; उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से तथ्य के निर्णयों को उलट नहीं करना चाहिए, अधिक समवर्ती, जब तक कि निचली अदालत द्वारा वापस किए गए निर्णय विकृत नहीं होते हैं, जो स्पष्ट रूप से मामला नहीं था; तैयारी और इच्छा के पहलू पर, सुखबीर सिंह बनाम बृज पाल सिंह 7 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया था कि विशिष्ट सी राहत के उन दो कारकों का अनुपालन करने के लिए भारी नकदी की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय ऐसा करने के लिए वित्तीय क्षमता की उपस्थिति है। ₹ 3,90,000-8 के लिए एक चेक रिकॉर्ड पर रखा गया है जो उस बैठक के लिए था जो उप-पंजीयक के कार्यालय में होने वाली थी, लेकिन वास्तव में यह प्रतिवादी थे जो उपस्थित नहीं हुए; उच्च न्यायालय ने तथ्य की बारीकियों को पलटने में गंभीर गलती की, विशेष रूप से निचली अदालत के रिकॉर्ड के अभाव में।

न्यायालय की राय

13. धारा 100, सी. पी. सी. पर न्यायशास्त्र समृद्ध और विविध है। समय-समय पर इस न्यायालय ने कई निर्णयों में उन आवश्यकताओं को निर्धारित किया है, जिन्हें उसमें निर्धारित दूसरी अपील के लिए अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, जिन्हें बनाए रखा जाना चाहिए और उसके बाद उन पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के समक्ष कई मामले हैं जो इस प्रावधान के अनुप्रयोग पर निर्भर करते हैं, हम सिद्धांतों को दोहराना आवश्यक समझते हैं।

13.1 इस धारा के तहत सबसे बुनियादी आवश्यकता "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" की उपस्थिति और उसे तैयार करना है। दूसरे शब्दों में, इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए इस तरह के प्रश्न का अस्तित्व अपरिहार्य है।⁹

13.2 इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का वर्णन इस न्यायालय द्वारा गुरदेव कौर बनाम काकी 10 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) में किया गया है जिसमें कहा गया है कि 1976 के संशोधन के बाद, धारा 100 सी. पी. सी. का दायरा बहुत कम हो गया है और प्रकृति में प्रतिबंधात्मक होने के लिए संकुचित हो गया है।^{द हाई}

7 (1997) 2 एससीसी 200 दो न्यायाधीशों की पीठ

8 73 को प्रदर्शित करें, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अंक संख्या 3 में दर्ज किया गया है।

9 पंचगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी और अन्य। (1997) 4 एस. सी. सी. 713 दो न्यायाधीश पीठ

10 (2007) 1 एस. सी. सी. 546 दो न्यायाधीश पीठ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल उस मामले में है जिसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, जो अपील के ज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से तैयार/निर्धारित किए गए हैं। यह देखा गया है कि:

"दूसरी अपील को स्वीकार करते समय, यह उच्च न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व है कि वह कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करे और उसके बाद ही उच्च न्यायालय को कानून के उन प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। संशोधित खंड में उपयोग की जाने वाली भाषा में शब्दों को "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" के रूप में शामिल किया गया है जो विधायी इरादे का संकेत है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विधायी इरादा बहुत स्पष्ट था कि विधायिका कभी भी दूसरी अपील को "तथ्यों पर तीसरा परीक्षण" या "जुआ में एक और पासा" नहीं बनाना चाहती थी। मुख्य रूप से, संशोधित धारा के अनुसार, संशोधन का प्रभाव था:

- (i) उच्च न्यायालय को दूसरी अपील को स्वीकार करने में केवल तभी न्यायसंगत ठहराया जाएगा जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो; (ii) इस तरह के प्रश्न को सटीक रूप से बताने के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न;
- (iii) अपील की सुनवाई से पहले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने का कर्तव्य उच्च न्यायालय पर डाला गया है;
- ((iv) धारा का एक अन्य भाग यह है कि अपील की सुनवाई केवल उसी प्रश्न पर की जाएगी।"

रामदेव कौर (सुप्रा) को रणधीर में संदर्भित किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था।

कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य। 11.

13.3 संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी 12 में तीन लोगों की पीठ

न्यायाधीश, जिनके बारे में कहा गया है कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है:—

क) जो पहले भूमि के कानून या बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा तय नहीं किया गया था।

11 (2019) 17 एस. सी. सी. 71; दो न्यायाधीशों की पीठ 12 (2001) 3 एस. सी. सी. 179 तीन न्यायाधीशों की पीठ 497

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटर [संजय करोल जे.] 498 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

ख) मामले के निर्णय पर सामग्री का प्रभाव; और (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

केरल सरकार बनाम में ऐसे सिद्धांतों का पालन किया गया है।

जोसेफ 13 और चंद्रभान बनाम सरस्वती 14.

13.4 कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों (प्रश्नों) का गैर-निर्माण कार्यवाही को "स्पष्ट रूप से अवैध" बनाता है। उमरखान बनाम में इस न्यायालय के निर्णय।

बिमिल्लाबी 15 और शिव कोटेक्स बनाम तिर्गुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। 16.

इस स्थिति को इंगित करें।

14. उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के पर्याप्त प्रश्नों का उत्तर उसमें उठाए गए तर्कों के आलोक में दिया जाना चाहिए।

14.1 यदि न्यायालय का विचार है कि तैयार किए गए प्रश्न को बदला जाना है, हटाया जाना है या एक नया प्रश्न जोड़ा जाना है, तो न्यायालय को पक्षों को सुनना चाहिए। 14.2 उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के लिए, गजराबा का संदर्भ दिया जा सकता है।

भीखुभा वढेर बनाम सुमारा उमर अमाद 17 जहाँ निम्नलिखित

सिद्धांतों का पालन किया गया:—क) उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कारणों के साथ दिया जाना चाहिए। उसी का जवाब दिए बिना अपील का निपटारा करना उचित नहीं हो सकता है।

ख) यदि किसी प्रश्न को संशोधित करने, बदलने या हटाने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उसके संबंध में पक्षों को सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।

14.3 जब मामला स्वीकार किया जाता है, लेकिन सुनवाई के बाद जब यह पाया जाता है कि विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसी बर्खास्तगी में कारण दर्ज किए जाने चाहिए।

13 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 961 दो न्यायाधीशों की पीठ 14 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1273 दो न्यायाधीशों की पीठ 15 (2011) 9 एस. सी. सी. 684 दो न्यायाधीशों की पीठ

16 (2011) 9 एस. सी. सी. 678 दो न्यायाधीश पीठ 17 (2020) 11 एस. सी. सी. 114 (तीन न्यायाधीश पीठ)

15. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम.रूफ्राइट (पी) लिमिटेड 18 में यह देखा गया:

"4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के प्रावधानों की ओर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहां दूसरी अपील के लिए प्रतिवादी को यह तर्क देने की अनुमति है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है, अर्थात् पहले तैयार किए गए प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर दूसरी अपील पर आदेश को इंगित करना चाहिए, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, प्रारंभिक चरण में तैयार किए गए प्रश्न, अंतिम सुनवाई के चरण में, कानून के प्रश्न क्यों नहीं पाए गए थे।" 16. पर्याप्त प्रश्नों को आम तौर पर, बाद के चरण में तैयार नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो पक्षों को उनसे मिलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

यू. आर. विरूपाक्षप्पा बनाम सर्वमंगला 19 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"15. ... इसके अलावा, इसे आम तौर पर कोई कारण बताए बिना और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बाद के चरण में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार नहीं करना चाहिए।

उत्तरदाताओं। [नूने प्रसाद बनाम नूने रामकृष्ण (2008) 8 एस. सी. सी. देखें।

258 : (2008) 10 स्केल 523]; पंचगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी [(1997) 4 एससीसी 713] (एससीसी पैरा 8 और 9); और क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट [(1997) 5 एससीसी 438] (एससीसी पैरा 10 और 12)]।

16. हालाँकि, इस मामले में उच्च न्यायालय ने खुली अदालत में निर्णय देते हुए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया। इससे पहले कि कानून का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया जा सके, पक्षों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। उन्हें मिलने का मौका दिया जाना चाहिए था। यद्यपि न्यायालय के पास बाद के चरण में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है जो दूसरी अपील के प्रवेश के समय तैयार नहीं किया गया था, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 से जुड़े परंतुक में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी।"

16.1 महबूब-उर-रहमान बनाम अहसानुल गनी 20 में यह न्यायालय,

धारा 100 (5) सी. पी. सी. के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नानुसार देखा गया:—

18 (2009) 16 एस. सी. सी. 280 तीन न्यायाधीश पीठ 19 (2009) 2 एस. सी. सी. 177 दो न्यायाधीश पीठ 20 (2019) 19 एस. सी. सी. 415 दो न्यायाधीश पीठ 499

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटर [संजय करोल जे.] 500

क) उप-धारा (5) के परंतुक के तहत कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनवाई करना नियम नहीं है, चाहे तैयार किए गए प्रश्न (प्रश्न) कुछ भी हों, ताकि धारा 100, सी. पी. सी. की अन्य आवश्यकताओं को निरस्त किया जा सके।

16.2 यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस धारा का अनुप्रयोग केवल तभी होता है जब कुछ प्रश्न, जो कानून में महत्वपूर्ण हैं, पहले से ही तैयार किए जा चुके होते हैं। (बी. सी.

शिवशंकर बनाम बी. आर. नागराज 21)।

16.3 प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का गलत अनुप्रयोग, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए योग्य नहीं होगा और न ही तथ्यों के गलत अनुप्रयोग के लिए।

16.4 यदि किसी मुद्दे पर, निचली अदालत साक्ष्य पर चर्चा करती है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं देती है, तो उच्च न्यायालय धारा 100, सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र में है।

ऐसा कर सकते हैं। गोविंदभाई छोटाभाई पटेल बनाम पटेल रमनभाई माथुरभाई का संदर्भ दिया जाए।²²

कोंडीबा दगडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर 23 में यह न्यायालय,

अवलोकन किया—“6. यदि एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में वर्णित कानून का प्रश्न पहले से ही संबंधित उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, तो मामले के तथ्यों पर इसके केवल गलत आवेदन को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जाएगा। जहां कानून का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है या किसी तथ्यात्मक प्रारूप के अभाव में पक्षों के बीच उत्पन्न होता हुआ पाया गया है, वहां एक वादी को दूसरी अपील में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्य या प्रविष्टियों के अर्थ और दस्तावेज की सामग्री की केवल सराहना को कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं माना जा सकता है।

21 (2007) 15 एस. सी. सी. 387 दो न्यायाधीश पीठ 22 (2020) 16 एस. सी. सी. 255 दो न्यायाधीश पीठ 23 (1999) 3 एस. सी. सी. 722 दो न्यायाधीश पीठ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

16.5 असाधारण मामलों में अनुमत तथ्यों पर हस्तक्षेप, यानी जब तथ्य या तो अस्वीकार्य या कोई सबूत नहीं होने पर आधारित हो। इस न्यायालय ने दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली 24 मामले में विभिन्न अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा:—(क) उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं है जैसे कि यह पहला अपीलीय न्यायालय हो जब तक कि मामले विकृत न हों। (ख) तथ्य की खोज को असाधारण परिस्थितियों में नियमितता के बजाय दुर्लभता के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

ग) दूसरी अपील में साक्ष्य की जांच निषिद्ध नहीं है, लेकिन उचित निरीक्षण पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

17. दूसरी अपील के तहत अधिकारिता का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है। यह हमीदा बनाम मोहम्मद में देखा गया था। खलील 25 7.... उच्च न्यायालय, यह अच्छी तरह से तय है, धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, केवल इस आधार पर तथ्यों पर निचली अपीलीय अदालत के निर्णय को उलट नहीं सकता है कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पाए गए तथ्यों पर एक और दृष्टिकोण संभव था।”

इस स्थिति को अवतार सिंह और ओआरएस बनाम द्वारा दोहराया गया था। बिमला देवी और अन्य। 26.

17.1 इस तरह के प्रतिबंधित आवेदन की सहायता में, यह सुनिश्चित करने में एक आवश्यक पहलू है कि यह “तीसरी अपील” की प्रकृति को प्राप्त नहीं करता है, साक्ष्य की सराहना की सीमित संभावना है और संबंधित रूप से, तथ्य के समवर्ती तथ्यों को पलटने पर प्रतिबंध है। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा नजीर मोहम्मद बनाम जे. कमला 27 में बताए गए नियम के कुछ अपवाद हैं, जो इस प्रकार हैं:

“ 33.4. सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह एक पूर्ण नियम नहीं है। कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं जहाँ: (i) निम्न न्यायालयों ने भौतिक साक्ष्य की उपेक्षा की है या बिना किसी साक्ष्य के कार्य किया है; (ii) न्यायालयों ने आवेदन करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हैं।

24 (2010) 12 एस. सी. सी. 740 दो न्यायाधीश पीठ 25 (2001) 5 एस. सी. सी. 30 दो न्यायाधीश पीठ 26 (2021) 13 एस. सी. सी. 816 दो न्यायाधीश पीठ 27 (2020) 19 एस. सी. सी. 57 दो न्यायाधीश पीठ 501

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटर [संजय करोल जे.] 502

कानून गलत तरीके से; या (iii) अदालतों ने गलत तरीके से सबूत का बोझ डाला है। बिना किसी साक्ष्य के आधारित निर्णय, केवल उन मामलों को संदर्भित नहीं करता है जहां साक्ष्य की कुल कमी है, बल्कि उस मामले को भी संदर्भित करता है, जहां साक्ष्य, समग्र रूप से लिया गया है, तथ्य का समर्थन करने में यथोचित रूप से सक्षम नहीं है।"

17.2 उसी की सीमा को अवलोकन द्वारा रेखांकित किया जा सकता है

वह:

"32. दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय की अधिकारिता कानून के सारवान प्रश्न तक सीमित होने के कारण, तथ्य का एक निश्चित निष्कर्ष दूसरी अपील में चुनौती देने के लिए खुला नहीं है, भले ही साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत हो और तथ्य का निष्कर्ष गलत हो जैसा कि वी. रामचंद्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार [वी. रामचंद्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 303] में माना गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूरी तरह से नया मुद्दा, मामले में शामिल प्रश्न नहीं है, जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है।"

(जोर दिया गया) 18. उपरोक्त निकाले गए सिद्धांतों और संबंधित निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दूसरी अपील की परिकल्पना, न्यायालय की किसी भी अन्य प्रक्रिया की तरह, एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया के रूप में की गई है, प्रत्येक कदम आगे पिछले एक का परिणाम है। प्रवेश के चरण में महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना, अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना, उस पर सुनवाई और फिर एक तर्कपूर्ण निर्णय।

19. हालाँकि, जैसा कि विवादित निर्णय को पढ़ने से पता चलता है, इन कदमों का पालन किया गया, केवल आंशिक रूप से, और अधिक, इसमें निहित समय तत्व की अनदेखी करते हुए।

20. सुमारा उमर अहमद (ऊपर), किच्छा शुगर (ऊपर) और

विरूपाक्षप्पा (ऊपर) और गुरदेव कौर (ऊपर) द्वारा पहचानी गई सामग्री से पता चलता है कि प्रवेश के समय तैयार किए गए सभी प्रश्नों के साथ-साथ तैयार किए गए, जोड़े गए या बदले गए प्रश्नों पर पक्षकारों को सुनना बिल्कुल आवश्यक है। 21. वर्तमान मामले में, पक्षकारों को न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय नहीं दिया गया था। धारा 100 (5) सी. पी. सी. सुझाव देती है कि प्रवेश और सुनवाई में प्रश्नों को तैयार करने के बीच एक अंतर है, क्योंकि इसका परंतु न्यायालय को अतिरिक्त तैयार करने का अवसर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

सुनवाई के समय प्रश्न, जिन पर पक्षों को भी सुनना होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रवेश के समय तैयार किए गए प्रश्न, बाद में प्रश्न तैयार करने के ऐसे बिंदु पर पक्षकारों को पहले से ही ज्ञात हैं और उनके पास उसी पर तर्कों को संबोधित करने की तैयारी करने का समय है। यह बहस के दौरान है कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा खोजा जाता है और उस संबंध में एक प्रश्न तैयार किया जाता है, जिसमें पक्षों को उस प्रश्न को पूरा करने के लिए भी समय दिया जाता है।

22. हमारा विचार अमर सिंह बनाम दलीप सिंह 28 में समर्थन देता है जिसमें इस न्यायालय ने कहा था:-

क) कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने का उद्देश्य पक्षों को उस विशेष प्रश्न पर तैयार होने का अवसर देना है।

ख) जब न्यायालय द्वारा कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसे पक्षों को सूचित किया जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें उस पर तर्क देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ग) यदि सुनवाई के समय कोई अतिरिक्त प्रश्न तैयार किए गए थे, तो न्यायालय को उस प्रश्न पर भी पक्षों को सुनना चाहिए।

23. यहाँ, कानून के प्रश्नों को सुनवाई की दूसरी तारीख को तैयार किया गया था, पक्षों की सुनवाई ठीक उसी समय और वहाँ की गई थी, और दूसरी अपील का निपटारा किया गया था जिसमें निर्णय को निर्देशित किया गया था और तथ्यों को उलट दिया गया था। यह, जैसा कि उपरोक्त चर्चा में बताया गया है, दूसरी अपील के निपटारे के लिए निर्धारित तरीके के अनुरूप नहीं है।

24. विवादित निर्णय वादी की ओर से अनुबंध करने की तैयारी और इच्छा के संबंध में तथ्य के समवर्ती निर्णयों को उलट देता है, बिना किसी असाधारण परिस्थिति या आदेशों में विकृति को इंगित किए जो नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा वापस किए गए थे।

25. न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए, कानून के अनुसार, वास्तविक साक्ष्य, जो हमारे विचार में नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष था, की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि लौटाई गई वस्तुओं को विकृति के आधार पर वापस किया जाना है, तो उन्हें निश्चित रूप से अभिलेख से हटा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पहली अपील का न्यायालय "तथ्य का अंतिम न्यायालय" होने के नाते,

28 (2012) 13 एस. सी. सी. 405 दो न्यायाधीश पीठ 503

सुरेश लाटारुजी रामटेक बनाम साउ। सुमनबाई पांडुरंग पेटर [संजय करोल जे.] 504

केवल एक कहावत तक सीमित किया जाए, जिसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। आखिरकार, दूसरी अपील "तथ्यों पर तीसरा परीक्षण" नहीं है, और इसलिए, साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन के लिए न्यायसंगत होने के लिए, और उसी की आवश्यकता होने के लिए—साथ ही स्पष्ट रूप से, केवल एक "संभावित भिन्न दृष्टिकोण", विकृति या "कोई सबूत नहीं" या "अस्वीकार्य साक्ष्य" की अन्य शर्तों से अलग सीमा पर आग्रह किया जाना चाहिए, और बाद में, अदालत को आगे की दलीलों पर संतुष्ट होने के साथ, ऐसी संभावना के लिए, न्यायालय तब रिकॉर्ड के लिए बुलाने के लिए आगे बढ़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि केवल प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विकृति के तर्क को स्वीकार करना और अभिलेख की सराहना नहीं करना, प्रथम अपील के न्यायालय के लिए अनुचित होगा।

26. जिस जल्दबाजी में न्यायालय ने दलीलों को संबोधित करने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर के बिना अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। शासी कानून सभी प्रश्नों पर पक्षों को सुनने पर काफी जोर देता है—और यह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में परिलक्षित होता है। ऐसी अपीलों के निपटारे में न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

27. तत्काल अपील में उठाए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:

27.1 दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार में बैठे न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, प्रवेश के समय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना है। इस तरह के प्रश्न तैयार करने के बाद न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर पक्षकारों को सुनने के लिए आगे बढ़ेगा, यानी उन्हें मिलने और उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद। इस तरह की सुनवाई के बाद ही दूसरी अपील पर निर्णय लिया जाएगा।

27.2 सामान्य तौर पर, ऐसी अधिकारिता में उच्च न्यायालय तथ्य के निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि, यदि वह कानून के संबंध में ऐसा करने के लिए कोई सम्मोहक कारण बताता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन केवल निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखने के बाद, जिसके विश्लेषण पर ऐसे न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को पलटने की मांग की जाती है। दूसरे शब्दों में, तथ्य के तथ्यों को पलटते समय, न्यायालय को विचारण न्यायालय के अभिलेखों के लिए बुलाना होगा या यदि

अभिलेख पर रखा जाता है, तो उसी पर विचार करना होगा और उसके बाद ही नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता पर सवाल उठाना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

28. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजने का निर्णय लेते हैं।बॉम्बे (नागपुर पीठ) में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील No.324/2021 में पारित 30 सितंबर 2022 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय में बहाल कर दिया जाता है।तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और ऐसी शर्तों में इसकी अनुमति दी जाती है।

29. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।30. कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे